तेलंगाना: कांग्रेस ने 'अल्पसंख्यकों का घोषणापत्र' जारी किया

हैदराबाद, एजेंसी।

कांग्रेस की तेलंगाना इकाई ने कहा है कि यदि वह 30 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनावों में जीत हासिल करती है, तो सत्ता में आने के छह महीने के भीतर जाति आधारित जनगणना कराने के अलावा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए बजट को बढ़ाकर सालाना 4,000 करोड़ रुपये तक करेगी। 'अल्पसंख्यकों का घोषणापत्र' बृहस्पतिवार को जारी किया गया, जिसमें कहा गया है कि पार्टी नौकरियों, शिक्षा और सरकारी योजनाओं में अल्पसंख्यकों सहित सभी पिछड़े वर्गों के लिए उचित आरक्षण सुनिश्चित करेगी।

कांग्रेस ने इसके अलावा अल्पसंख्यक वर्ग के बेरोजगार युवाओं और महिलाओं को रियायती दर पर ऋण प्रदान करने के लिए प्रति वर्ष 1,000 करोड़ रुपये का प्रावधान करने का वादा किया। पार्टी ने कहा कि वह 'अब्दुल कलाम तोहफा-ए-तालीम योजना' के तहत मुस्लिम, ईसाई, सिख और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के युवाओं को एम.फिल और पीएचडी की पढ़ाई पूरी करने पर पांच लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। घोषणापत्र में इमाम, मुअज्जिन, खादिम, पादरी और ग्रंथी सहित सभी धर्मों के पुजारियों के लिए 10,000 रुपये से 12,000 रुपये का मासिक मानदेय देने की बात कही गई है।

भारत-चीन सीमा पर परिंदा भी पर न मार पाए: शाह

कहा, आईटीबीपी और सेना के जवान जब तक सीमा पर तैनात हैं तब तक देश की एक इंच भूमि को भी कोई कब्जा नहीं कर सकता

इंद्र वशिष्ठ

नई दिल्ली, मेट्रो मीडिया। केंद्र सरकार ने हवाई जहाज और रेल यात्रा में सेना की तर्ज पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए भी कोटा तय कर दिया है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के 62 वें स्थापना दिवस पर देहरादून में आयोजित समारोह को शुक्रवार को गृहमंत्री अमित शाह ने संबोधित किया।

गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि आज हुई नई शुरुआतों में से जवानों के लिए सेल्फ सस्टेनेबल एनर्जी बिल्डिंग और दुर्गम क्षेत्रों में ड्रोन सेवा की शुरुआत सबसे महत्वपूर्ण है। 17 हजार फीट की ऊंचाई पर बनी यह इमारत ठंडे मरुस्थल में एक आत्म निर्भर भारत का प्रतीक बनेगी। जब यहां पर बाहर का तापमान शून्य से 40-45 डिग्री नीचे चला जाता है। डीज़ल, केरोसीन का इस्तेमाल नहीं हो पाता, ऐसे में यह भवन 18 से 19 डिग्री तापमान में जवानों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराएगा। ऊंचाई वाले और दुर्गम क्षेत्रों में आईटीबीपी जवानों और सीमावर्ती गांव वालों के लिए दवाओं , खाद्य सामग्री और अन्य जरुरी वस्तुओं आदि की आपूर्ति के लिए ड्रोन के इस्तेमाल की शुरूआत शुक्रवार से हो गई। पहला

ड्रोन 15 किलो दवाईयां/ सब्जियां लेकर दुर्गम क्षेत्रों में पहुंचा।

गृहमंत्री ने कहा कि हिमालय सीमा क्षेत्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी हिमवीरों की है। 19 हजार फीट तक की ऊंचाई तक, माइनस 45 डिग्री तक तापमान, कम ऑक्सीजन में पैदल जा कर जवान बखूबी अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। जरुरत पड़ने पर सर्वोच्च बलिदान देने से भी पीछे न हटना आईटीबीपी की परंपरा रही है। गृहमंत्री ने कहा कि आईटीबीपी और सेना के जवान जब तक सीमा पर तैनात हैं तब तक देश की एक इंच भूमि को भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। ऐसा इनका इतिहास रहा है। अब हिमवीरांगनाएं /बेटियां भी देश की सीमा की सुरक्षा में कंधे से कंधा मिलाकर शामिल हो रही हैं।

गृहमंत्री ने कहा कि भारत विश्व का नेतृत्व करे अमृत काल में ऐसे भारत को साल 2047 तक बनाना है। भारत- चीन सीमा किस तरह से ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित हो हिमवीर इसके लक्ष्य गढे। साल 2047 तक परिंदा भी पर न मार पाए, इस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था खड़ी करें।

भारत- चीन सीमा पर अनेक प्रकार की दिक्कतें थी। साल 2014 से पहले भारत-चीन सीमा पर औसतन खर्च चार हज़ार करोड़ रुपये सालाना होता था। साल 2022-2023 में ये खर्च बढ़ कर तीन गुना 12340 करोड़ रुपये हो गया। पिछले 9 साल में भारत-चीन सीमा पर औसतन खर्च तीन गुना सालाना बढ़ाया गया है। सीमा पर सड़क, सीमा चौकी , जवानों की सुविधा बनाने के लिए और गांवों को संपूर्ण सुविधा युक्त गांव बनाने के लिए औसतन तीन गुना खर्च सालाना बढ़ाया गया है।

भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को बहाल करने की सिफारिश

नई दिल्ली, एजेंसी।

संसद की एक स्थायी समिति ने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को प्रस्तावित नयी न्याय संहिता में बहाल किये जाने की सिफारिश की है जबकि उच्चतम न्यायालय की पांच सदस्यीय पीठ इसे संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों के विरुद्ध करार दे चुकी है। गृह मामलों पर विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष एवं राज्य सभा में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सदस्य बृजलाल द्वारा शुक्रवार को यहां उप राष्ट्रपति एवं राज्य सभा के सभापति जगदीप धनखड़ को सौंपी गयी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रस्तावित भारतीय न्याय संहिता के उद्देश्यों के मद्देनजर भारतीय दंड संहिता धारा 377 फिर से शामिल करना और बनाये रखना अनिवार्य है। इस धारा

में अप्राकृतिक यौन संबंधों को अपराध माना गया था।

उसके विरुद्ध दंड के प्रावधान किये गये थे। इसको चुनौती देने वालों का कहना था कि इसकी वजह से समलैंगिक जोड़ों को समाज में अपराधी के रूप में देखा जाता है और उनके साथ भेदभाव का बर्ताव होता है। इसे एक संस्था ने गैर संवैधानिक करार देने के लिये 2001 में दिल्ली

एक रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रस्तावित भारतीय न्याय संहिता के उद्देश्यों के मद्देनजर भारतीय दंड संहिता धारा 377 फिर से शामिल करना और बनाये रखना अनिवार्य है।

उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। समिति ने भारतीय न्याय संहिता 2023 संबंधी अपने 286 वें प्रतिवेदन में कहा है कि नवजोत सिंह जौहर बनाम भारत सरकार (2018) मामले में उच्चतम न्यायालय की पांच सदस्यीय पीठ ने सर्वसम्मति से माना कि धारा 377 संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन है।

इसके बावजूद इस धारा के उपबंध वयस्कों के साथ असहमति वाले शारीरिक संभोग, नाबालिगों के साथ इस तरह के सभी कृत्यों और वहशीपनों के कृत्यों के मामले में लागू हैं। समिति ने कहा,हालांकि, अब भारतीय न्याय संहिता 2023 में पुरुष, महिला ,ट्रांसजेंडर के साथ असहमति वाले यौन अपराध और वहशिता के लिये कोई उपबन्ध नहीं किया गया है। प्रतिवेदन में कहा गया है, समिति महसूस करती है कि भारतीय न्याय संहिता के उद्देश्यों और कारणों के कथन मंस बताये गये उद्देश्यों के साथ तालमेल बिठाने के लिये भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को फिर से शामिल करना और बनाये रखना अनिवार्य है जो अन्य बातों के साथ समलैंगिक रूप से तटस्थ अपराधों की दिशा में परिकल्पित कदम पर प्रकाश डालता है।

एमएसएमई क्षेत्र ने 15 करोड़ से अधिक रोजगार दिये

नई दिल्ली,एजेंसी। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने कहा है कि छोटे उद्योग क्षेत्र में 15 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है और इनमें से 3.4 करोड़ महिलाएं हैं। राणे ने गुरुवार को एक ट्वीट में कहा कि एमएसएमई क्षेत्र ने 15 करोड़ से अधिक रोजगार के अवसर पैदा करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। राणे ने उद्यम पोर्टल पर तीन करोड़ से अधिक एमएसएमई इकाइयों के पंजीकरण की सुविधाजनक का उल्लेख किया। उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत 99 लाख अनौपचारिक एमएसएमई इकाइयां भी शामिल हैं। इन तीन करोड़ पंजीकृत एमएसएमई में से 41 लाख से अधिक महिला स्वामित्व वाले एमएसएमई हैं।

केंद्र ने डिजिटल विज्ञापन नीति 2023 को दी मंजूरी

नई दिल्ली, एजेंसी।

सूचना और प्रसारण (आई एंड बी) मंत्रालय ने सरकार की विज्ञापन शाखा केंद्रीय संचार ब्यूरो (सीबीसी) को डिजीटल मीडिया स्पेस अभियान चलाने में सक्षम और सशक्त बनाने के लिए डिजिटल विज्ञापन नीति 2023 को मंजूरी दे दी है। नई नीति ने सीबीसी को ओटीटी और वीडियो ऑन डिमांड स्पेस में एजेंसियों तथा संगठनों को सूचीबद्ध करने में भी सक्षम बनाया है। आईबी मंत्रालय ने शुक्रवार को एक मीडिया विज्ञप्ति में कहा,"यह नीति उभरते मीडिया परिदृश्य और मीडिया उपभोग के बढ़ते डिजिटलीकरण के जवाब में केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और नीतियों के बारे में जानकारी प्रसारित करने और जागरूकता पैदा करने के सीबीसी के मिशन में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिह्नित करती है।

मध्य प्रदेश और राजस्थान सहित कुछ प्रमुख राज्यों में विधानसभा चुनावों के बीच केंद्र सरकार की डिजिटल विज्ञापन नीति आई है।

इसके अलावा, आम चुनाव अगले साल की शुरुआत में होने हैं। सीबीसी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत काम करता है और देश में विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों, योजनाओं और नीतियों के बारे में जागरूकता पैदा करने और जानकारी प्रसारित करने के लिए जिम्मेदार है।

एक नजर

हम मिजोरम विधानसभा चुनाव जीतेंगे: जोरामथंगा

आइजोल,एजेंसी। मिजोरम के मुख्यमंत्री और मिजो नेशनल फ्रंट के नेता जोरामथंगा ने शुक्रवार को विश्वास जताया कि उनकी पार्टी विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करेगी। जोरामथंगा ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद उनकी पार्टी अधिक कुशल तरीके से और नये जोश के साथ अगले पांच साल तक राज्य की सेवा करेगी।

मिजोरम की 40 सदस्यीय विधानसभा के लिए सात नवंबर को चुनाव हुए थे। मिजोरम में मतों की गिनती तीन दिसंबर को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और राजस्थान विधानसभा चुनाव की मतगणना के साथ होगी।

जोरामथंगा ने यहां एमएनएफ कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, हम ईश्वर और जनता की मदद से सत्ता में बने रहेंगे।

हम और कुशल ढंग से और नये जोश के साथ अपने राज्य की अगुवाई और सेवा करेंगे।

जोरामथंगा (79) ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में राज्य ने कोविड-19 महामारी, भूकंप , सीमा विवाद और पड़ोसी देशों से घुसपैठ जैसी कई समस्याओं का सामना किया।

उन्होंने कहा,लेकिन, हमने लोगों की मदद के लिए अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। ईश्वर ने एक बार फिर हमें हमारी वर्तमान स्थिति में पहुंचाया है।

प्रौद्योगिकी में प्रगति के साथ तालमेल स्थापित करे: जनरल पांडे

नई दिल्ली, एजेंसी।

थलसेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने सैन्य अभियंता सेवाएं (एमईएस) से आग्रह किया है कि वह रक्षा उद्योग में हो रही प्रौद्योगिकीय प्रगति के साथ तालमेल बिठाए और आधुनिक निर्माण विधियां अपनाए। रक्षा सूत्रों ने बताया कि उन्होंने 8 और 9 नवंबर को दिल्ली छावनी के मानेकशॉ सेंटर में, बुनियादी ढांचा विकास और रखरखाव पर आयोजित दो दिवसीय इंजीनियर सम्मेलन में अपने संबोधन में यह बात कही। उन्होंने बताया कि जनरल पांडे ने थलसेना, नौसेना, वायुसेना और तटरक्षक, एमईएस के लगभग 550 अधिकारियों, निर्माण उद्योग, शिक्षा और अनुसंधान संगठनों के प्रतिनिधियों की एक सभा को संबोधित किया।

जनरल पांडे ने मुख्य भाषण देते हुए, उद्योग में हो रही तकनीकी प्रगति के साथ तालमेल बिठानेर और ₹आधुनिक प्रगति को अपनानेर का प्रयास करने का एमईएस से आग्रह किया। सूत्रों ने बताया कि उन्होंने कुछ मूलभूत मुद्दों पर प्रकाश डाला, जिनपर एमईएस को गौर करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इनमें ज्ञान का आदान-प्रदान करना, अन्य सरकारी विभागों और बाहरी एजेंसियों से संपर्क के जरिये समय बचाने के लिए आधुनिक परियोजना प्रबंधन के तरीके ढूंढना तथा प्रौद्योगिकी के उपयोग से निर्माण की गुणवत्ता में सुधार करना शामिल हैं।

नगालैंड के पूर्व राज्यपाल पद्मनाभ आचार्य चल बसे

मुंबई,एजेंसी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता और नगालैंड के पूर्व राज्यपाल पद्मनाभ आचार्य का शुक्रवार को यहां निधन हो गया। पार्टी सूत्रों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कर्नाटक के उडुपी के रहने वाले आचार्य ने यहां अपने घर पर अंतिम सांस ली। वह 92 वर्ष के थे।

वयोवृद्ध भाजपा नेता आचार्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) के साथ भी काम कर चुके थे। आचार्य नगालैंड, त्रिपुरा और असम के राज्यपाल रहे थे। उन्होंने मणिपुर और अरूणाचल प्रदेश के राज्यपाल की जिम्मेदारियां भी संभाली थीं।

मोदी से ऐसी भाषा की उम्मीद नहीं, जनता कांग्रेस के साथ: गहलोत

जयपुर, एजेंसी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बयान पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री से इस तरह की भाषा की उम्मीद नहीं थी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा नेता ऐसी बातों को मुद्दा बना रहे हैं जो मुद्दा ही नहीं है। गहलोत ने कहा कि इन विधानसभा चुनाव में राज्ये की जनता कांग्रेस के साथ है और वह फिर सरकार बनाएगी।

प्रधानमंत्री मोदी ने बृहस्पतिवार को उदयपुर के पास एक चुनावी सभा में कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर हमला बोलते हुए राज्य की कांग्रेस सरकार को आतंकियों से सहानुभूति रखने वाली सरकार बताया था। गहलोत ने यहां मीडिया से कहा, जो प्रधानमंत्री जी बोले हैं

बहुत ही अस्वीकार्य है हम लोगों को। और मैं नम्र निवेदन करना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी से कि कृपा करके इस प्रकार का माहौल नहीं बनाएं देश के लिए, (यह) देश के हित में नहीं है, समाज के हित में नहीं है।

गहलोत ने आगे कहा, 'हमारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी तो है नहीं। यह विचारधारा की लड़ाई हमारी। यह लड़ाई विचारधारा तक सीमित रहनी चाहिए। प्रोग्राम, पॉलिसी की बात करें, इश्यू की बात करें ...नॉन इश्यू को इश्यू बना रहे हो आप लोग। आप इस प्रकार से धर्म के नाम पर लोगों को भड़का रहे हो अभी से। उन्होंने कहा, 'जिस भाषा में उन्होंने कहा है मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये उम्मीद नहीं करता था। इसलिए मैंने कहा कि या तो उन्हें ग़लत ब्रीफिंग की गई है यह वे जान बूझ कर घबरा गए हैं बौखला गए हैं जानबूझ ये जुमला बोला है मेरा यह मानना है।

गहलोत ने कहा कि राजस्थान में इस समय माहौल कांग्रेस के पक्ष में है और उसकी शानदार योजनाओं व कार्यक्रमों की चर्चा पूरे देश में है। मुख्यमंत्री ने बाद में पाली के बाली में चुनावी सभा में भी दोहराया कि भाजपा के पास कोई चुनावी मुद्दा नहीं है और जनता कांग्रेस के साथ है। उन्होंने विश्वास जताया कि राज्य में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी। गहलोत ने कहा कि पांच वर्षों में सबको साथ लेकर चलते हुए प्रदेश के सर्वांगीण विकास में कोई कमी नहीं रखी है।

राजस्थान में दलित महिलाओं पर भयंकर अत्याचार हो रहा: सीतारमण

इंदौर, एजेंसी।

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा पर हमला बोलते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को यहां कहा कि कांग्रेस शासित राजस्थान में दलित महिलाओं पर 'भयंकर अत्याचार' हो रहे हैं, लेकिन वह (प्रियंका) दूसरे राज्यों में जाकर व्याख्यान दे रही हैं। प्रियंका ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी की रैलियों में आरोप लगाया है कि सूबे में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के 18 साल के राज में महिलाओं से बलात्कार की घटनाएं बढ़ी हैं।

सीतारमण ने पलटवार करते हुए इंदौर में संवाददाताओं से कहा, राजस्थान में, खासकर दलित महिलाओं पर इतने भयंकर अत्याचार हो रहे हैं कि टीवी और

अखबारों में इसकी खबरें देखकर डर लगता है। इस बारे में राजस्थान सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने कहा लेकिन प्रियंका इस विषय में कुछ नहीं बोलतीं। वह राजस्थान जाकर मुख्यमंत्री (अशोक गहलोत) से सवाल नहीं करतीं।

लेकिन दूसरे राज्यों में जाकर व्याख्यान देती हैं।'' सीतारमण ने एक सवाल के जवाब में कहा कि 1984 के सिख विरोधी दंगों के बाद कांग्रेस की ओर से माफी किसी और ने नहीं, बल्कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मांगी थी जो खुद एक सिख हैं। भाजपा की वरिष्ठ नेता ने कहा कि सिख विरोधी दंगों के मुकदमों को कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों ने ठंडे बस्ते में डाल दिया था और केंद्र में भाजपा की सरकार बनने के बाद ये मामले दोबारा खुले और अदालतों ने इनमें फैसला सुनाया।

सीतारमण ने कहा कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को भी सिख विरोधी दंगों के मामले में सिखों की ''चीख-पुकार'' सुननी चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि राज्य की ₹लाड़ली बहना योजना₹ को ''मुफ्त की रेवड़ी'' बताया जाना सही नहीं है क्योंकि इसका बजटीय प्रावधान किया गया है और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के जरिये इसकी सहायता राशि महिला हितग्राहियों के बैंक खातों में भेजी जा रही है।

वित्त मंत्री ने कहा, ''भाजपा उन योजनाओं का चुनावी वादे किये जाने के खिलाफ है, जिनका न तो बजट में प्रावधान किया जाता है, न ही विधानसभा में उन पर चर्चा की जाती है।

उम्मीद से ज्यादा बहुमत मिलेगा: पायलट

जयपुर,एजेंसी। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने शुक्रवार को कहा कि चुनाव अभियान में मिल रहा मतदाताओं का रुझान बेहद उत्साहजनक है और कांग्रेस का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है।

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिस उम्मीद से पार्टी चुनाव लड़ रही है, उसे उससे ज्यादा बहुमत मिलेगा। टोंक में जनसम्पर्क के दौरान पायलट ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा '' हमारा चुनावी अभियान बड़ा सकारात्मक है.. हमने जो घोषणाएं और जनकल्याण की बात रखी है उसे जनता पसंद कर रही है और कांग्रेस के उम्मीदवारों के प्रचार में लगातार भीड़ आ रही है।' उन्होंने कहा ''चुनाव अभियान बहुत अच्छा चल रहा है और मतदाताओं तथा कार्यकर्ताओं से मिल रहा रुझान बेहद उत्साहजनक है।

मैं ऐसा मानता हूं कि कांग्रेस का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। जिस उम्मीद से हम चुनाव लड़ रहे हैं उससे ज्यादा बहुमत लेकर हम लोग निकलेंगे।

Morning Glory Leasing and Finance Limited

CIN:L67120DL1984PLC018872 , Website: www.morninggloryleasing.in
Regd. Off: IRIS House 16 Business Centre, Nangal Raya, New Delhi-110046.
Email: morninggloryleasing@gmail.com, Ph: 011- 4711 9100

Statement of Standalone Unaudited Financial Results For The Quarter and Half Year Ended September 30, 2023 (₹ in Lakhs)

Sl. No.	Particulars	Standalone			
		For the Quarter Ended on 30-09-2023	For the Quarter Ended on 30-09-2022	For the Half Year Ended on 30-09-2023	For the Year Ended on 31-03-2023
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total income from Operations	2.14	2.74	3.39	5.00
2	Net Profit for the period (before Tax & Exceptional items)	1.43	1.82	2.10	2.74
3	Net Profit for the period (before Tax after Exceptional items)	1.43	1.82	2.10	2.74
4	Net Profit for the period (after Tax after Exceptional items)	1.31	1.35	1.81	2.03
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit for the Period after Tax and Other Comprehensive Income after Tax)	(35.22)	(88.59)	(21.38)	8.33
6	Paid up Equity Share Capital (Face value of Rs.10/- each)	24.9	24.90	24.90	24.9
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	-	636.06
8	Earnings Per Share (of ₹ 10/- each) (For continuing and discontinued operations) (Not Annualised)				
	1. Basic (amount in Rs.)	(13.71)	(35.58)	(7.95)	3.35
	2. Diluted (amount in Rs.)	(13.71)	(35.58)	(7.95)	3.35

NOTES :
1. The above results were reviewed and recommended by the Audit Committee and then approved by the Board of Directors at their meeting held on 10th November, 2023. The unaudited financial results for the quarter and Six Months ended September 30,2023 have been limited reviewed by the Statutory Auditors of the Company.
2. The above is an extract of the detailed format of unaudited quarterly financial results filed with the stock exchanges under regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation,2015. The full format of the unaudited quarterly financial results is available on the stock exchange websites (URL-www.msei.in) and also on above mentioned Company's website at https://www.morninggloryleasing.in.
3. There is no change(s) in accounting policies which impact on net profit/loss, total comprehensive income or any other relevant financial item(s).
4. Exceptional items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind-AS Rules.

For and on behalf of the Board of Directors of
Morning Glory Leasing and Finance Ltd
Sd/-
Rajesh Bagri
Managing Director and Chief Financial Officer

Place: New Delhi
Date: 10th November, 2023

राजनीति | समर्थकों का दावा कि लाल सिंह डोगरों की है एक मजबूत आवाज

चौधरी लाल सिंह की गिरफ्तारी पर विपक्ष की खामोशी पर उठ रहे हैं सवाल

सतीश वर्मा

जम्मू, मेट्रो मीडिया। धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए के आरोप में देश के कई नेता एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी के रडार पर हैं। बल्कि कई तो जेल में भी बंद है। परंतु, सूत्रों का कहना है कि जम्मू कश्मीर में दो बार के सांसद तथा तीन बार पूर्ववर्ती राज्य सरकारों में कैबिनेट मंत्री रहे चौधरी लाल सिंह संभवत पहले सियासी नेता हैं, जोकि मनी लांड्रिंग मामले में व ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए और उनका दीपों का त्यौहार दीपावली ईडी की गिरफ्तारी में ही कटेगा। यह जुदा बात है कि कमोबेश तमाम विपक्षी दलों का आरोप है कि ईडी केंद्र सरकार के इशारे पर केवल विपक्षी नेताओं का उत्पीड़न करने में लगी है। चौधरी लाल सिंह के परिजन से लेकर उनके समर्थक भाजपा के वरिष्ठ नेता पर चौधरी लाल सिंह का उत्पीड़न करवाने का आरोप लगाने में लगे हैं।

दिलचस्प बात यह है कि चौधरी लाल सिंह के इस मामले को लेकर जम्मू तथा घाटी का कोई भी विपक्षी नेता उनके समर्थन में खुलकर कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। हां, विपक्ष नेता इतना जरूर कहते हैं कि उन्हें ईडी, सीबीआई अथवा इनकम टैक्स आदि की किसी भी जांच पर कोई एतराज नहीं है लेकिन असल सवाल यह है कि यह एजेंसियां केवल विपक्ष नेताओं के पीछे क्यों

पड़ी है। मालूम हो कि कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला तथा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रवक्ता एडवोकेट रविंद्र शर्मा इस प्रकरण के बाद चौधरी लाल सिंह के घर उनके परिजनों को मिलने गए थे। पूछने पर इन नेताओं का कहना था कि वह उनके परिजनों का हाल-चाल जानने गए थे। काबिलेगौर है कि ईडी टीम द्वारा चौधरी लाल सिंह के कठुआ स्थित निवास पर हुई रेड के बाद उनसे की गई पूछताछ और फिर गिरफ्तारी के बाद से उनके समर्थकों का लगातार आक्रोश तथा विरोध प्रदर्शन जारी है। उनके समर्थकों में इस बात का भी असंतोष है कि चौधरी लाल सिंह की गिरफ्तारी पर विपक्षी नेता क्यों खामोश है। उनका यह भी कहना है कि यदि यह विपक्षी नेता आज खामोश रहेंगे तो कल को उन पर भी इन सरकारी एजेंसियों की गाज गिर सकती है।

इन समर्थकों का यह भी कहना है कि क्योंकि चौधरी लाल सिंह डुग्गर और डोगरो की एक बुलंद आवाज है इसलिए उन्हें खामोश करने के लिए इसमें फसाया जा रहा है। कहा गया कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की ओर से कठुआ स्थित आरबी एजुकेशनल ट्रस्ट से जुड़े एक कथित बड़े भूमि घोटाले मामले में चौधरी लाल सिंह को गिरफ्तार किया गया है। इस एजुकेशनल ट्रस्ट की चेयरपर्सन चौधरी लाल सिंह की धर्मपत्नी एवं पूर्व एमएलए कांता अंडोत्रा हैं। कामता और दूसरा वह उनके परिवार का एक अन्य सदस्य 30 नवंबर तक जमानत पर हैं। सूत्रों का कहना है कि आने वाले दिनों में प्रदेश के कुछेक और प्रमुख नेताओं पर भी शिकंजा कसा जा सकता है।

SUPERIOR INDUSTRIAL ENTERPRISES LIMITED

Regd. Office: 25,Bazar Lane, Bengali Market, New-Delhi-110001
CIN: L15142DL1991PLC046469, Tel. No.: 011-43585000, Fax: 011-43585015
E-mail: info@superiorindustrial.in, Website: www.superiorindustrial.in

Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter and Half Year Ended 30th September,2023
Regulation 47(1)(b) of SEBI (LODR), 2015

(Rs. In Lacs)

Sl. No.	Particulars	Standalone			Consolidated		
		Quarter ended 30.09.2023 Unaudited	Quarter ended 30.09.2022 Unaudited	Half Year ended 30.09.2023 unaudited	Quarter ended 30.09.2023 Unaudited	Quarter ended 30.09.2022 Unaudited	Half Year ended 30.09.2023 unaudited
1.	Total Income from Operations	336.92	352.03	808.95	968.99	1409.22	2979.38
2.	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	119.41	48.30	189.50	108.71	102.28	256.50
3.	Net Profit/(Loss) for the period (after Exceptional and/or Extraordinary items)	119.41	48.30	189.50	177.68	108.33	321.91
4.	Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	119.41	48.30	189.50	176.97	108.33	323.33
5.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after Tax) and other Comprehensive Income (after tax)	117.83	48.50	188.77	177.06	108.67	323.21
6.	No. of Equity Share Capital (face value of Rs.10/- per share)	138.5	138.5	138.5	138.5	138.5	138.5
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	-	-	-	-
8.	Earnings Per Share (of Rs. 10/-each) for continuing and discontinuing operations) Basic:	0.86	0.35	1.37	1.32	0.56	2.10
	Diluted:	0.86	0.35	1.37	1.32	0.56	2.10

Notes :- 1. The above is an extract of the detailed format of the standalone and consolidated unaudited financial results for the quarter and half year ended on 30th September, 2023 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of standalone and consolidated financial results is available on the Stock Exchanges' websites-(www.bseindia.com) and the Company's website (www.superiorindustrial.in).
2. The above unaudited financial results were reviewed by the Audit Committee and thereafter approved at the meeting of the Board of Directors held on 10th November,2023.

By order of the Board of Directors For and on behalf of
Superior Industrial Enterprises Limited
Sd/-
Kamal Agarwal
Managing Director
DIN:02644047

Place : New Delhi
Date : 10th November, 2023